ई. ए. साथ्यानेसन

बनाम

वी. के. अग्निहोत्री और अन्य

18 दिसंबर, 2003

[न्यायाधिपति एस. बी. सिन्हा और न्यायाधिपति अरुण कुमार]

सेवा कानूनः पदोन्नति-आरक्षण-रिक्तियों के आधार पर 40-पॉइंट रोस्टर लागू करने के रेलवे के फैसले को ट्रिब्यूनल-ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनौती दी गई जिसमें कहा गया कि आरक्षण का सिद्धांत निचली श्रेणी में आरक्षित और अनारक्षित श्रेणियों की तुलना में कैडर की ताकत और वरिष्ठता पर काम करता है। आरक्षण के आधार पर पहले की पदोन्नति के साथ नहीं बल्कि पदोन्नत श्रेणी में परिलक्षित होगा - रेलवे द्वारा दायर एसएलपी खारिज कर दी गई क्योंकि मामला न्यायाधिपति सभरवाल* और न्यायाधिपति अजीत सिंह** द्वारा कवर किया गया था - अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए ट्रिब्यूनल ने पाया कि न्यायाधिपति सभरवाल और न्यायाधिपति अजीत सिंह के मामले में निर्णय को भावी प्रभाव से लागू करने हेतु निर्देशित किया गया

माना गया कि ट्रिब्यूनल ने गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करने से इनकार करके स्पष्ट त्रुटि की है। इस आधार पर कि सभरवाल और अजीत सिंह-एल को एक संभावित ऑपरेशन दिया गया था-जिस हद तक उक्त निर्णयों को संभावित रूप से संचालित करने के लिए निर्देशित किया गया था, उसे अजीत सिंह-द्वितीय में पर्याप्त रूप से समझाया गया है और एमजी बडप्पनवर-ट्रिब्यूनल में इस कारण से दोहराया गया है 6 सितंबर 1994 के फैसले में, अधिकारियों और रेलवे प्रशासन को उन मुद्दों के संदर्भ में राहत देने का निर्देश दिया गया, जिनमें निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है - यह स्थिति होने के कारण, यदि आवश्यक हो तो दिशा-निर्देश उचित और उचित होंगे। ट्रिब्यूनल द्वारा जारी किया जाएगा.

*आर के सभरवाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य [1995] 2 एससीसी 745 , समझाया और भरोसा किया।

**अजीत सिंह जानुजा और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य ए.आई.आर(1996) एस. सी. 118- [1996] 2 एस. सी. सी.715; अजीत सिंह-ii बनाम पंजाब राज्य, [1999] 7 एस. सी. सी. 209 और एम. जी. बडप्पनवर और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य [2001] 2 - एस. सी. सी. 666, पर भरोसा किया।

भारत संघ और अन्य बनाम विरपाल सिंह चौहान और अन्य [1995] 6 एससीसी 684 और जे. सी. मलिक बनाम भारत संघ, (1978) 1 एस. एल. आर. 844 (सभी) संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5629/1997

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, केरल के सी.पी. में एर्नाकुलम बेंच में (सी) क्रमांक 68/96 ओ.ए. 1991 की संख्या 483 में दिनांक 25.2.97 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी के लिए सी. एस. राजन, फजलिन अनम और ई. एम. एस. अनम

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदक इसमें अपीलार्थी है। आवेदक ने न्यायाधिकरण के समक्ष एक मूल आवेदन दायर किया जिसमें सवाल उठाया गया था भारत संघ के रेलवे प्रशासन का 40-बिंदु सूची को रिक्तियों के आधार पर लागू करने का निर्णय, न कि पदोन्नति के संवर्ग की संख्या के आधार पर। यह विवाद में नहीं है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की विभिन्न पीठों द्वारा दिए गए बड़ी संख्या में निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय दिया कि आरक्षण को पदोन्नति स्तर पर लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती

है और आगे रोस्टर पॉइंट पर कैडर की संख्या को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए न कि रिक्तियों को। इसका निर्देशन किया गया थाः

"उदाहरणों का पालन करते हुए, हम मानते हैंः

(क) कि आरक्षण का सिद्धांत संवर्ग पर चलता है।

(ख) निचली श्रेणी के कर्मचारियों की आरक्षित और अनारक्षित श्रेणियों की तुलना में वरिष्ठता पदोन्नत श्रेणी में दिखाई देगी, आरक्षण के आधार पर प्राप्त पिछली पदोन्नति के साथ भी नहीं।

इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, उत्तरदाता-रेलवे राहत पर काम करेगा। हम निर्देश जारी कर रहे हैं, क्योंकि शीर्ष अदालत ने सोचा था कि लागू निर्णयों को लागू किया जाना चाहिए। (सी. ए. 2017/78 में अंतरिम आदेश)

भारत संघ ने इसके खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता दी जिसे एसएलपी (सी) संख्या 10691/1995 के रूप में चिह्नित किया गया था, और एक आदेश द्वारा- दिनांक 31 तारीख(एस. आई. सी.) अगस्त, 1996 में उक्त याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया थाः

" देरी को माफ कर दिया गया।

ये मामले पूरी तरह से आर. के. सभरवाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य [1995] 2 एस. सी. सी. 745 और अजीत सिंह जानुजा और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य ए आई आर (1986) एस सी 1189 मामलों में इस न्यायालय के फैसले में शामिल हैं। इसलिए विशेष अनुमति याचिकाएं हैं खारिज कर दिया गया।"

इसके बाद अपीलकर्ता ने ट्रिब्यूनल के समक्ष अवमानना याचिका दायर की क्योंकि उसके 8 सितंबर, 1994 के पहले के आदेश को उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर लागू नहीं किया गया था। हालाँकि, ट्रिब्यूनल ने 30 अगस्त 1996 के अपने आदेश में इस अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए यह मत व्यक्त किया गया कि जैसा कि 'सभरवाल' (ऊपर) और अजीत सिंह-I (ऊपर) दोनों के मामले में, निर्णय को संभावित प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया था, अपीलार्थी यह कहते हुए किसी भी राहत के हकदार नहीं थेः

"विशेष अनुमति याचिकाओं को बिना किसी कारण के खारिज नहीं किया गया था। शीर्ष न्यायालय ने एसएलपी को खारिज करने का कारण बताया है। जब ऐसा कारण दिया जाता है, तो निर्णय वह बन जाता है जो संविधान के अनुच्छेद 141 को आकर्षित करता है जो प्रदान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा।“

न्यायाधिकरण ने, उपर्युक्त मामलों में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करने का तात्पर्य रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया कि यहाँ उत्तरदाताओं को इसके निर्देशों की अवज्ञा करने और अवमानना करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण ने इस न्यायालय के फैसलों को गलत तरीके से पढ़ा और गलत तरीके से लागू किया, जिसमें कहा गया कि इस न्यायालय द्वारा सुभरवाल और अजीत सिंह-I में दिए गए पूरे फैसले को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था। अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील सही प्रतीत होता है।

आर. के. सभरवाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य [1995] 2 एससीसी 745 इस न्यायालय के समक्ष दो दलीलें उठाई गईं जो हैंः

(1) आरक्षण का उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्गों को सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करना है और इस तरह उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदान किए गए किसी भी तंत्र का उस उद्देश्य से संबंध होना चाहिए जिसे प्राप्त किया जाना चाहिए। सटीक तर्क यह है कि आरक्षण का प्रतिशत निकालने के लिए अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग से संबंधित पदोन्नतियों/नियुक्तियों को गिना जाना चाहिए, चाहे वे सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध नियुक्त किए गए हों या आरक्षित पदों के विरुद्ध

नियुक्त किए गए हों। दूसरे शब्दों में यदि 14% से अधिक अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करके अपनी योग्यता/वरिष्ठता के आधार पर एक कैडर में नियुक्त/पदोन्नत किया जाता है, तो उक्त कैडर में आरक्षण का उद्देश्य प्राप्त हो जाने पर, आरक्षण प्रदान करने वाले सरकारी निर्देश निष्क्रिय हो जाएंगे।

(2) एक बार अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए निर्धारित पद और रोस्टर में पिछड़े वर्गों को भरा जाता है और आरक्षण पूरा हो जाता है। रोस्टर आगे काम नहीं कर सकता है और इसे बंद कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद किसी संवर्ग में खाली होने वाला कोई भी पद होना चाहिए उस श्रेणी से भरा गया-आरक्षित या सामान्य-सेवानिवृत्ति आदि के कारण जिसके सदस्य का पद खाली हो गया था।

अपीलकर्ताओं की ओर से उठाए गए पहले तर्क को स्वीकार नहीं किया गया था। हालाँकि, दूसरे विवाद को निम्नानुसार निपटाया गया

"हम संभावित परिणाम की जांच कर सकते हैं यदि किसी संवर्ग में कुल पदों को दाखिल करने के बाद उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के संबंध में रोस्टर को संचालित करने की अनुमति दी जाती है। 100 अंकों के रोस्टर में, विभिन्न रोस्टर बिंदुओं पर 14 पद अनुसूचित जाति/अनुसूचित के बीच से दाखिल किए जाते हैं। अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए, 2 पद पिछड़े वर्गों से भरे जाते हैं और शेष 84 पद सामान्य श्रेणी से भरे जाते हैं।

मान लीजिए कि 100 पदों वाले कैडर के सभी पदों को 31.12.1994 द्वारा रोस्टर के अनुसार भरा जाता है। इसके बाद वर्ष 1995 में, 25 सामान्य श्रेणी के व्यक्ति (84 में से) सेवानिवृत्त होते हैं। पुनः वर्ष 1996 में, सामान्य श्रेणी से संबंधित 25 और व्यक्ति सेवानिवृत्त हुए। जो स्थिति सामने आएगी वह यह होगी कि अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग 50 रिक्तियों में से 16 प्रतिशत हिस्सेदारी का दावा करेंगे। यदि उन्हें 8 रिक्तियां दी जाती हैं तो 100 पदों के संवर्ग में आरक्षित श्रेणियों के पास 24 पद होंगे जिससे आरक्षण 16 प्रतिशत से बढ़कर 24 प्रतिशत हो जाएगा। इसके विपरीत यदि रोस्टर को तब तक संचालित करने की अनुमति दी जाती है जब तक कि संवर्ग में कुल पद नहीं भर जाते हैं और उसके बाद संवर्ग में आने वाली रिक्तियों को उसी श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा भरा जाना है जिनकी सेवानिवृत्ति आदि के कारण रिक्तियां हुई हैं तो आरक्षित श्रेणी के बीच संतुलन और, सामान्य श्रेणी को हमेशा बनाए रखा जाएगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि रोस्टर बिंदु पर आरक्षित उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में यह राज्य सरकार के लिए खुला होगा कि वह मुद्दे को उचित और निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ा इसमें इस न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर भी विचार किया। जे. सी. मलिक बनाम भारत संघ, [1978] 1 एस. एल. आर. 844 (सभी), जिसे न्यायाधिकरण द्वारा उपरोक्त निर्णय में भी संदर्भित किया गया है।

हालाँकि, ऐसा कहने के बाद, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि व्याख्या रोस्टर के काम करने के संबंध में और उक्त बिंदु पर निष्कर्ष संभावित रूप से प्रभावी होंगे। इस प्रकार, जो संभावित बनाया गया था वह निर्णय का अनुप्रयोग था।

भारत संघ और अन्य बनाम विरपाल सिंह चौहान और अन्य [1995] 6 एस. सी. सी. 684 सभरवाल (ऊपर) का उल्लेख करते हुए इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

"यह आंशिक रूप से इसलिए हो सकता है क्योंकि यह नियम अब आर. के. में लागू किया गया है। सभरवाल, [1995] 2 एस. सी. सी. 745 का पालन नहीं किया जा रहा था। यह भी हो सकता है कि ऐसा परिणाम (i) और (ii) में उल्लिखित कारकों के संयुक्त संचालन द्वारा लाया गया हो। तथ्य यह है कि स्थिति - यह मानते हुए कि यह वही है जो सामान्य उम्मीदवारों द्वारा वर्णित है - को अब पूर्वव्यापी प्रभाव से ठीक नहीं किया जा सकता है। संविधान पीठ ने आर.के. सभरवाल ने भी निर्देशन किया है कि उसमें प्रतिपादित नियम का केवल भावी संचालन होगा। जहां तक मौजूदा अपीलों का सवाल है, यह निर्देश देना पर्याप्त है कि रेलवे अधिकारी फैसले की तारीख से नियम (i), (ii) और (iii (पैरा नंबर 29 में बताए गए) का पालन करेंगे। आर. के. सभरवाल में निर्णय की तारीख, अर्थात, 10.2.1995।"

" विद्वान वकीलों ने हमारे समक्ष कुछ अपीलों के व्यक्तिगत तथ्यों को हमारे ध्यान में लाने की मांग की है, लेकिन हम इसका प्रस्ताव नहीं करते हैं उन तथ्यों को दर्ज करें या उन पर कोई घोषणा करें।"

विद्वान वकील ने हमारे सामने कुछ अपीलों के व्यक्तिगत तथ्यों को हमारे ध्यान में लाने की मांग की है, लेकिन हम उन तथ्यों में प्रवेश करने या उस पर कोई घोषणा करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। हमारी विचाराधीन राय में उचित कदम इन सभी को भेजना है उपरोक्त तीन सिद्धांतों को लागू करते हुए संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों पर काम करने के लिए मामलों को ट्रिब्यूनल में वापस भेज दिया जाता है। उपरोक्त शर्तों के अनुसार अपीलों का निपटारा किया जाता है और मामलों को संबंधित ट्रिब्यूनल को भेज दिया जाता है। रिट याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं। कोई लागत नहीं।"

फिर भी अजीत सिंह जनुजा और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य [1996] 2 एससीसी 715 में इस न्यायालय ने सभरवाल के मामले के साथ-साथ अन्य निर्णय का भी उल्लेख किया, जो इस प्रकार है:

"ऐसे में यह मानना तर्कसंगत, उचित और उचित होगा कि जब सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को बाद में निचले ग्रेड से उच्च ग्रेड में पदोन्नत किया जाता है, तो उसे अनुसूचित जाति/जनजाति के उस उम्मीदवार से वरिष्ठ माना जाएगा जो पहले था। उनके लिए आरक्षित पद

के विरुद्ध त्वरित पदोन्नति दी गई। जब भी अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित पद को और भी उच्च ग्रेड में भरने का प्रश्न उठता है तो अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐसे उम्मीदवार को पहले पदोन्नत किया जाएगा, लेकिन जब विचार चल रहा हो सामान्य श्रेणी के पद के विरुद्ध इससे भी ऊंचे ग्रेड में प्रस्ताव के संबंध में, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को, जिसे बाद में पदोन्नत किया गया है, वरिष्ठ माना जाएगा और वरिष्ठता-सह-योग्यता या योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत को लागू करते हुए पदोन्नति के लिए उसके मामले पर पहले विचार किया जाएगा। यदि यह नियम एवं प्रक्रिया लागू नहीं की गई तो परिणाम भुगतने होंगे ऐसा हो कि अधिकांश पद उच्च ग्रेड में रखे जायेंगे। एक स्तर पर ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिन्होंने न केवल आरक्षण और रोस्टर के आधार पर सेवा में प्रवेश किया है, बल्कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को केवल उनकी प्रारंभिक त्वरित पदोन्नति के आधार पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों पर पदोन्नत होने से बाहर कर दिया है। यह संविधान के अनुच्छेद 16(4) या अनुच्छेद 335 की आवश्यकता या भावना के अनुरूप नहीं होगा।

हमारे अनुसार, जसवंत सिंह बनाम पंजाब सरकार के सचिव के मामले में पूर्ण पीठ का यह कहना उचित नहीं था कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को उनकी पूर्व पदोन्नति के आधार पर सामान्य श्रेणी के पदों

पर विचार न करने पर संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 का प्रभाव पड़ेगा। उस दृष्टिकोण को इंद्रा साहनी के मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इस न्यायालय के फैसले के साथ-साथ आर.के. के मामले में संविधान पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचार के खिलाफ माना जाएगा। सभरवाल तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है और जसवक्त सिंह बनाम पंजाब सरकार के सचिव के मामले में पूर्ण पीठ के फैसले का वह हिस्सा उलट दिया गया है।"

इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय अजीत सिंह-द्वितीय बनाम पंजाब राज्य, [1999] 7 एससीसी 209 मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष व्याख्या के लिए आए। इस न्यायालय ने मामले पर विस्तार से विचार किया।

आयोजित : इसलिए, हमारा मानना है कि रोस्टर-पॉइंट प्रमोटी (आरक्षित श्रेणी) अपने से वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में पदोन्नत पद पर लगातार कार्यभार संभालने की तारीख से पदोन्नत श्रेणी में अपनी वरिष्ठता की गणना नहीं कर सकते हैं।" निचली श्रेणी में और जिन्हें बाद में पदोन्नत किया गया। दूसरी ओर, निचले स्तर पर वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार, यदि वह पदोन्नति स्तर पर बाद में लेकिन आरक्षित उम्मीदवार की आगे पदोन्नति से पहले पहुंचता है - तो उसे पदोन्नति स्तर पर आरक्षित उम्मीदवार से वरिष्ठ माना जाएगा, भले ही आरक्षित

उम्मीदवार को पहले उस स्तर पर पदोन्नत किया गया था। हम इसे बिंदु 3 के तहत आगे समझाएंगे। हम यह भी मानते हैं कि वीरपाल [1995] 6 एससीसी 684 और अजीत सिंह [1996] 2 एससीसी 715 का निर्णय सही ढंग से किया गया है और जगदीश लाल का निर्णय सही ढंग से नहीं किया गया है। बिंदु 1 और 2 तदनुसार तय किए गए हैं।

"सभरवाल" और "अजीत सिंह-I" के संभावित ऑपरेशन की व्याख्या और प्रभाव के संबंध में, इसे क्रमशः निम्नानुसार रखा गया था।

"यह सेवा न्यायशास्त्र में स्वयंसिद्ध है कि किसी भी कोटा से अधिक गलत तरीके से की गई किसी भी पदोन्नति को तदर्थ माना जाएगा। यह आरक्षण कोटा पर उतना ही लागू होता है जितना कि यह सीधी भर्ती और पदोन्नत मामलों पर लागू होता है; यदि कोई अदालत केवल इसी क्रम में निर्णय लेती है कठिनाइयों को दूर करें ऐसे रोस्टर-प्वाइंट पदोन्नतियों को प्रत्यावर्तन का सामना नहीं करना पड़ता है, तो हमारी राय में, यह मानना आवश्यक होगा - अनुच्छेद 14 और 16(1) की व्याख्या के बिना - कि ऐसे पदोन्नत व्यक्ति किसी भी अतिरिक्त लाभ के अनुदान के लिए अनुरोध नहीं कर सकते हैं रोस्टर के गलत अनुप्रयोग से वरिष्ठता का प्रवाह। हमारे विचार में, जबकि अदालतें पिछली अधर्मिता से उत्पन्न होने वाली तत्काल कठिनाई से राहत दे सकती हैं, अदालतें वरिष्ठता जैसे अतिरिक्त लाभ नहीं दे सकती हैं जिनमें तत्काल कठिनाई का कोई तत्व नहीं है। इस प्रकार,

जबकि 10.2.1995 से पहले की गई रोस्टर से अधिक पदोन्नति सुरक्षित है, ऐसे पदोन्नत व्यक्ति वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते। ऐसे अतिरिक्त रोस्टर-प्वाइंट पदोन्नतियों के पदोन्नति संवर्ग में वरिष्ठता की समीक्षा 10.2.1995 के बाद की जाएगी और केवल उस तारीख से गणना की जाएगी जिस दिन उन्हें अन्यथा सामान्य पदोन्नति मिल जाती। किसी आरक्षित उम्मीदवार द्वारा पहले से रखे गए पद पर उत्पन्न होने वाली किसी भी भविष्य की रिक्ति में। यह सभरवाल के संबंध में 'संभावना' बिंदु का निपटान करता है।

"जहां 1.3.1996 से पहले, यानी लेवल 3 पर अजीत सिंह के फैसले की तारीख, आरक्षित उम्मीदवार थे जो पहले वहां पहुंचे थे और बाद में पहुँचने वाले वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार भी थे (लेकिन इससे पहले कि आरक्षित उम्मीदवार को स्तर 4 पर पदोन्नत किया गया था) और जब इस तथ्य के बावजूद कि वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार को स्तर 3 पर वरिष्ठ माना जाता था (अजीत सिंह को देखते हुए), आरक्षित उम्मीदवार को स्तर 4 पर और पदोन्नत किया जाता है-इस तथ्य पर विचार किए बिना कि वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार स्तर 3 पर भी उपलब्ध था, तब 1.3.1996 के बाद, स्तर 3 की समीक्षा करना आवश्यक हो जाता है। आरक्षित उम्मीदवार को स्तर 4 पर पदोन्नत करना और उस पर पुनर्विचार करना (आरक्षित उम्मीदवार जो 1.3.1996 से पहले स्तर 4 तक पहुँच गया था, उसे उलट

दिए बिना)। जैसे-जैसे वरिष्ठ आरक्षित उम्मीदवार को बाद में स्तर 4 में पदोन्नत किया जाता है, स्तर 4 पर वरिष्ठता को भी इस आधार पर फिर से निर्धारित किया जाना चाहिए कि स्तर 3 पर आरक्षित उम्मीदवार को उनकी सामान्य पदोन्नति कब मिली होगी, उन्हें स्तर 3 पर वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार से कनिष्ठ माना जाता है। चंदर पाल बनाम हरियाणा राज्य, [1997] 10 एस. सी. सी. 474 को ऊपर बताए गए तरीके से समझना होगा।

इसी स्थिति को इस न्यायालय ने एम.जी.बडप्पनवार और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य [2001] 2 एससीसी 666 में निम्नलिखित शब्दों में दोहराया था:

"रोस्टर पदोन्नति के संबंध में वरिष्ठता को गिनने की अनुमति देने वाला कोई विशिष्ट नियम नहीं है। अजीत सिंह-I में एक परिपत्र जो रोस्टर-प्वाइंट पदोन्नतियों को वरिष्ठता देता था, उसे अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन माना गया था। वीरपाल में जो था बाद में निर्णय लिया गया, इस न्यायालय ने 'यह राज्य के लिए खुला है' शब्दों का इस्तेमाल किया और यह धारणा दी कि राज्य रोस्टर-प्वाइंट पदोन्नतियों को वरिष्ठता दे सकता है। लेकिन अजीत सिंह-द्वितीय में इस पहलू को स्पष्ट कर दिया गया है। यह माना गया कि वरिष्ठता नियम जैसे नियम 2(सी), 4 और 4-ए, जो प्रारंभिक पदोन्नति की तारीख से वरिष्ठता की गणना करने की

अनुमति देते हैं, बुनियादी स्तर पर वरिष्ठता, वरिष्ठता-सह-फिटनेस या वरिष्ठता-सह द्वारा नियमों के अनुसार की जाने वाली सामान्य पदोन्नति को नियंत्रित करते हैं। -योग्यता या चयन द्वारा, लेकिन रोस्टर के माध्यम से की गई पदोन्नति के लिए नहीं।

पिछड़े वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व के सीमित उद्देश्य के लिए सेवा के विभिन्न स्तरों पर। यदि नियमों की व्याख्या की जानी है ऐसा माना जाता था कि रोस्टर पदोन्नति केवल सेवा के विभिन्न स्तरों पर पिछड़े वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व के सीमित उद्देश्य के लिए थी। यदि नियमों की व्याख्या रोस्टर-प्वाइंट पदोन्नतियों को वरिष्ठता प्रदान करने के तरीके से की जाती है, जो सामान्य चैनल से नहीं गुजरे हैं जहां बुनियादी वरिष्ठता या चयन प्रक्रिया शामिल है, तो यह माना गया कि नियम अधिकारातीत होंगे अनुच्छेद 14 और भारत के संविधान का अनुच्छेद 16. अनुच्छेद 16 (4-ए) भी मदद नहीं कर सकता. ऐसी वरिष्ठता, यदि दी जाए, यह असमानों के साथ समान व्यवहार करने के समान होगा, बल्कि समान से अधिक व्यवहार करने जैसा होगा।"

उपरोक्त आधिकारिक घोषणा को देखते हुए हमारे पास यह अभिनिर्धारित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था कि न्यायाधिकरण ने गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करने से इनकार करने में एक स्पष्ट त्रुटि की, इस आधार पर कि सभरवाल और

अजीत सिंह-प्रथम को एक संभावित कार्यवाही दी गई थी। जैसा कि ऊपर देखा गया है, उक्त निर्णयों को किस हद तक संभावित रूप से संचालित करने के लिए निर्देशित किया गया था, अजीत सिंह-द्वितीय में पर्याप्त रूप से समझाया गया है और एम. जी. बडप्पनवर (उपरोक्त) में दोहराया गया है।

हालाँकि, हम देख सकते हैं कि ऊपर उद्धृत निर्णयों में, इस न्यायालय ने व्यक्तिगत मामलों में जाने से इनकार कर दिया है और पक्षों को न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी शिकायतें व्यक्त करने का निर्देश दिया है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, न्यायाधिकरण ने 6 सितंबर 1994 के फैसले के आधार पर अधिकारियों और रेलवे प्रशासन को मुद्दों के संदर्भ में राहत देने का निर्देश दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका अनुपालन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति होने के कारण, यदि न्यायाधिकरण द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं तो यह उचित और उपयुक्त होगा। हम आशा और विश्वास करते हैं कि यह मामला न्यायाधिकरण के समक्ष लंबे समय से लंबित है

इस पर शीघ्र विचार किया जाएगा। इसलिए, हमारी राय है कि आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार इसे रद्द किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है. चूंकि उत्तरदाताओं ने

उपस्थिति दर्ज नहीं की है इसलिए हम लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देते हैं।

आर.पी.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।